THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b) The Government will give priority to the Right to Work in the Eighth Five Year Plan, and the Plan is at the stage of formulation.

The Government will strive to ensure for all citizens the Right to Work to enable them to earn a livelihood and to become participants in the task of nation building.

CBI inquiry against Government servants

1744. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of investigations launched by CBI against Government servants during the last three years; and

(b) the number of cases which have been finalised during the same period and with what results?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) During the last three years, 3667 investigations have been launched by CBI.

(b) During the same period, 3577 investigations have been finalised resulting in:—

(1) Prosecution	:	1380
(2) Regular Departmental action	:	1702
(3) Sent to Departments for such action as deemed fit.	:	349
(4) Preliminary inquiries converted into regular cases.	:	141
(5) Closure	:	205

पूर्वी दिल्ली के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

1745. श्री सुनील कुमार पटटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली के दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के शिक्षण कार्यक्रम में काफी गतिरोध उत्पन्न हुआ है और यदि हां, तो रिक्त पड़े इन पदों के विद्यालय-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त पदों को कब तक भरा जायेगा और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या यह भी सच है कि इन विद्यालयों में उचित फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में इन रिक्त पदों को भरने तथा फर्नीचर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (**प्रो० एम०जी०के० मेनन**) : (क) पूर्वी दिल्ली में स्थापित विभिन्न स्कूलों में चार सौ उनहत्तर (४६९) अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। रिक्त पड़े हुए पदों के स्कूलवार आंकड़े से संबंधित सूचना शिक्षा विभाग द्वारा नहीं रखी जाती। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों के अध्ययन में कोई हानि न हो संबंधित स्कूलों द्वारा आंतरिक कार्यकरण संबंधी प्रबंध किए जाते हैं।

(ख) और (ग) पदों का भरना एक सतत् प्रक्रिया है तथा दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें आशा है कि रिक्त पद जुलाई, 1990 के अंत तक भर दिए जाएंगे। दिल्ली प्रशासन ने फर्नीचर की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को पहले से ही आर्डर दे दिए हैं।

Amount of grants sanctioned to different institutions by DSWAZ and CSWB

1746. SHRI SUNIL KUMAR PATTNAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state what is the amount of grants sanctioned to various institutions for "Family Advisory Centres" in Delhi by the "Central Social Welfare Board" during the year 1984, the institutions whose sanctions have been cancelled without any